भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4187
उत्तर देने की तारीख : 26.03.2025

असम में पीएम विकास

4187. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना के आरंभ से लेकर अब तक पीएम विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है और असम को आवंटित तथा उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम विकास के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में चिह्नित कला एवं शिल्प समूहों की संख्या कितनी है और उन्हें जारी की गई निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के आरंभ से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत प्रमाणपत्र प्राप्त कर विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या असम में पीएम विकास योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों के बीच प्रशिक्षण के बाद रोजगार सृजन तथा उद्यमिता गतिविधियों का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण या अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम में, विशेष रूप से दूरदराज तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीएम विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद' और 'हमारी धरोहर' योजनाओं को समायोजित करती है तथा निम्नलिखित के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है:

i. कौशल एवं प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)
ii. महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता
iii. शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
iv. बुनियादी ढांचा विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

इस योजना में लाभार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रस्तावित ऋण कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के तहत मंत्रालय को कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और परियोजनाओं का चयन करने और उनको अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ङ): मंत्रालय, इस योजना के तहत, इच्छुक एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय हुनर हाट और लोक संवर्धन पर्व, प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि जैसी पहलों के माध्यम से अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता भी फैला रहा है।

*****